Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

आईसीडब्ल्यूए अतिथि खंड

भारत और पाकिस्तान: बाकी है उम्मीद

राजदूत राजीव डोगरा

9 जनवरी 2016

थोड़ी समय के लिए और बड़े ही अजीब तरीके से शांत बरकरार थी। लगता है आतंकवादियों के पीछे हटने के आसार थे, घुसपैठ की खबरों में कमी थीं और प्रवक्ताओं के लिए सुकून वाले दिन थे। यहां तक कि मीडिया में बहस-मुबाहिसा करने वालों के पास भी हाय-तौबा मचाने के लिए कुछ खास नहीं था। गुप्त बैठकों की एक अलग किस्म की सुगबुगाहट थी; और यह हैरानी की भी बात थी। कुछ समय के लिए लोगों ने इसे एक नई सुबह के संकेत के रूप में लिया; तो क्या यह तूफान से पहले का सन्नाटा था? और लग रहा था नेतृत्व ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फिर पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ। रिश्ते में एक बार फिर से ठहराव आ गया। लोग बातचीत की आवश्यकता पर सवाल उठाने लगे। अब यह तर्क नहीं था कि 'अगर बातचीत नहीं हुई, तो क्या होगा?' अब यह मांग होने लगी, 'हमारे बीच बातचीत क्यों होनी चाहिए? अब तक इससे हमने क्या हासिल किया है?'

लेकिन विदेश मामलों की मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 16 दिसंबर 2015 को संसद को सूचित किया था; "युद्ध कोई विकल्प नहीं है,"

शांति की खोज के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातचीत पर्दे में भी आयोजित की जा रही थी। दोनों में से कोई भी पक्ष मीडिया में अपना मुंह नहीं खोल रहा है। दरअसल, पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बावजूद भारत ने अपने बयानों में बहुत ही संयम बरता है और उसके बाद अफगानिस्तान में मजार-ए-शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ।

कुल मिला कर मीडिया भी वार्ता जारी रखने के पक्ष में हैं। और दोनों देशों के लोगों की पसंद को देखते हुए शांति बरकरार रखे जाने की संभावना है। बाहरी दुनिया को भी थोड़ी राहत महसूस हुई; क्योंकि दो परमाणु से लैस पड़ोसियों के बीच हर बार तनाव बढ़ने से चिंता होना लाजिमी है।

एक सामान्य मान्यता है कि दो दुश्मनों के बीच गतिरोध की स्थिति नहीं होनी चाहिए; धारदार हथियार के बीच बातचीत करना जोखिम भरा होता है। लेकिन तब क्या होगा अगर दोनों पक्ष फिर से डगमगा जाएं? पठानकोट में आतंकी हमला काफी हिला देनेवाला था, लेकिन अगर पाकिस्तान में बैठे इसके मास्टर-माइंड के खिलाफ संतोषजनक और समयबद्ध कार्रवाई की भारत की मांग की अनदेखी की गयी तो क्या होगा? या अगर एक और बड़ा आतंकी हमला होता है तो क्या होगा?

तो क्या हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे, जहां कभी थे, और भारत के लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा? उस घटना में दूसरों के उदाहरण हैं, जिन्होंने उकसावे और कड़वे विवाद के दौरान अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की।

पेरिस में आतंकी हमले के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति होलांदे ने घोषणा की, "हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं।" इसके बाद आईएसआईएस के लक्ष्यों के खिलाफ फ्रांसीसी हमला जोर पकड़ने लगा।

नवंबर 2015 में एक रूसी लड़ाकू जेट को तुर्की ने गोली मार कर गिरा दिया था, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसका बदला लिया। रूस ने तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलायी।

अमेरिका ने लगभग हमेशा उन लोगों का पीछा किया और उनका सफाया किया है, जिन्होंने अपने फैसले से उसके हितों और उसके नागरिकों को धमकाया है या नुकसान पहुंचाया है।

प्राचीन काल से ही ऐसी पुख्ता प्रतिक्रिया दरअसल, पश्चिमी नीति के अनुरूप है। सिसेरो ने एक बार चेतावनी देते हुए कहा था; "जिस दिन रोमन साम्राज्य अपने नागरिकों में से किसी एक का भी बचाव करने में विफल रहा, वह दिन रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत के तौर पर जाना जाएगा।" पश्चिमी दुनिया ने इस उक्ति का बखूबी पालन किया है।

इस मामले में पाकिस्तान और अरब दुनिया भी ऐसी ही है। 2011 में अमेरिकी हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के मद्देनजर पाकिस्तान ने अमेरिका को खूब खरी-खोटी सुनाया। इसी तरह पश्चिम में, खाड़ी में, यमन के साथ सऊदी अरब के युद्ध का मुद्दा और कुछ नहीं, बस उस पर अपनी मर्जी थोपने का है। और जब तेहरान में सऊदी अरब दूतावास पर हमला हुआ, तब उसने ईरान के साथ तुरंत अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया।

फिर भी, बार-बार उकसाने पर भी भारत ने उदासीन रवैया अपनाया। और इसने पाकिस्तान से पैदा हुए आतंकवाद का जवाब देने के लिए एक अलग रास्ता अख्तियार किया है। इस तथ्य के बावजूद कि आधुनिक इतिहास में शायद ही कोई दूसरा उदाहरण है, जहां एक छोटा-सा देश अपने विशाल पड़ोसी को हजारों जख्म देने और खून बहाने की अपनी नीति पर लगातार कायम है।

सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देने के बदले भारत के प्रति किसी तरह के सौजन्यता बरतने से इंकार करना उकसावे की एक बहुत ही छोटी-सी मिसाल है। पिछले तीन दशकों से पाकिस्तान सरकार और उसके प्रतिनिधियों ने कहीं पर भी किसी भी तरह से संभव हो भारतीय आर्थिक हितों नुकसान पहुंचाया है और उसके नागरिकों पर हमला किया है। इससे भारत को मानवीय और भौतिक दोनों ही तरह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा।

ऐसे बहुत ही दुर्लभ अवसर हैं, जब इसने कार्रवाई करने की धमकी दी हो, वहीं सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इसने आखिरी बार जवाब दिया था।

भारत ने पहले चरम कार्रवाई के बारे में सोचा, लेकिन फिर अंतिम समय में हिचकिचा गया, दस महीने की लंबी सोच-विचार के बाद उसने इरादा बदल लिया। भारत द्वारा किया गया यह एकमात्र काम उसकी बेबसी को इस तरह दर्शाता है कि पाकिस्तान के छद्म युद्ध का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसका और सबूत मिला, जब 26/11 के हमले के बाद बातचीत, जिसका पाकिस्तान बेसब्री इंतजार कर रहा है, की गुंजाइश

अपने आप खत्म हो गयी। इसलिए कई लोगों को तब बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, जब श्रीमती स्वराज ने घोषणा की कि 'युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है।'

लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? अव्वल तो भारत से बात करने का मतलब है कि अब वह 'वैश्विक स्तर पर बदनाम देश' नहीं रहा, यह वह टैग जो 26/11 के बाद से उस पर लगा हुआ है। दूसरा, यह स्वीकृति मिलने और बातचीत की शुरुआत होने से कश्मीर की समस्या और सियाचिन से भारतीय सेनाओं की वापसी का मुद्दा फिर से आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है।

विडंबना यह है कि भारत द्वारा बातचीत के संदर्भ से आतंकवाद का मामला अलग कर देने से पाकिस्तान को दोहरा लाभ हुआ; एक, भारत से उसे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र मिला, और दूसरा, इस नाते उसके आतंकवाद के एजेंडे को फिर से आगे बढ़ाने की संभावना बनी।

16 दिसंबर को सुषमा स्वराज ने भी कहा था, "हमने तय किया है कि बातचीत के माध्यम से हम आतंकवाद की समस्या का हल निकालेंगे; क्योंकि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, जिससे आतंकवाद का साया दूर हो।"

ऐसा हो सकता है, लेकिन इतिहास का बोझ इससे उल्ट सलाह देता है। यह चेतावनी देता है कि 1947 के बाद से पाकिस्तान की हरकतों का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है; अतीत में अपने वादों पर शायद ही यह कभी खरा उतरा है। हाल के इतिहास से मिसाल का हवाला है, एक चालू किस्म की धारणा यह है कि 2004 के बाद की अवधि थोड़ी सुकून वाली थी; क्योंकि मुशर्रफ ने वादा किया था कि भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तानी भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल, उनकी बात में कोई दम नहीं था। 2004 से 2008 के बीच की अवधि में भारत के खिलाफ कुछ बेहद खतरनाक आतंकी हमले हुए। मुशर्रफ के अच्छे व्यवहार के वादे के बावजूद ऐसा हुआ।

हालांकि इस बड़े ही जटिल, भावना से भरपूर इस रिश्ते में आतंक केवल एक पहलू है। कभी-कभी लोगों को हैरानी होती है यह सोच कर कि इन जटिलताओं का जवाब देने के लायक भारत की नीति में पर्याप्त गुंजाइश है भी या नहीं।

***